



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४७]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी २०, १९७९/फाल्गुन १, १९००

No. ४७]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 1979/PHALGUNA 1, 1900

इस भाग में चिन्ह पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि पहले भाग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उच्चाग्र भंशालय

(शोधानिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, २० फरवरी, १९७९

संकल्प

विषय :—दृष्टकरण वित के लिए भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली के पुनरीक्षण के लिए अध्ययन वल।

सं० ६ (९)/७८-को-आप—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० ६/७/७७-को-आप दिनांक २८ प्रक्रमावर, १९७७ द्वारा हृषकरण वित के लिए भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली को गहराई में अध्ययन करने तथा योजना के कार्यों को सुचारू रूप से बलाने के लिये उचित सिफारिशें करने हेतु डा० एम० शी० हाटे की अध्यक्षता में एक अध्ययन वल गठित किया था। इस अध्ययन वल की रचना निम्न प्रकार से थी :—

1. डा० एम० वीत हाटे, मुख्य अधिकारी, कृषि और विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक।
2. श्री शी० सी० पट्टायक, उपसचिव, बैंकिंग संकाय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, वित मंत्रालय।
3. श्री एम० एम० बन्ना, निदेशक (वस्त्र), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
4. श्री शी० शंकर, शार्झ० ए० एस०, निदेशक, हृषकरण और वस्त्र तामिल नाडु सरकार।

5. श्री एम० एन० शुक्ल, निदेशक, हृषकरण, उत्तर प्रदेश सरकार।
6. श्री एम० शी० पिटों, निदेशक, हृषकरण व वस्त्र, महाराष्ट्र सरकार।
7. श्री शी० शी० मोहन्सी, निदेशक, हृषकरण व वस्त्र, उडीसा सरकार।
8. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार सरकार।
9. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक, अनंटपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक, आर्थि प्रबेश।
11. श्री एल० शी० सप्तश्रृणि, हृषकरण उप विकास आयुक्त, सरस्वति।

2. अध्ययन वल के निम्नलिखित कार्य विषय थे :—

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्वित से, सहकारी समितियों/बैंकों के द्वारा हृषकरण बुनकरों को वित्तीय सहायता देने की योजना की कार्यप्रणाली का सामान्य पुनरीक्षण करना तथा यदि प्रावधानक ही सो, इस योजना के कार्यों में संशोधन का सुझाव देना तथा योजना के कार्यों में सुधार लाना।
- (ग) हृषकरण बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिए अपेक्षित ऋण की राशि निर्धारित करने में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निर्भार्त जाने वाली विशिष्ट भूमिका का अध्ययन करना तथा इस उद्देश्य के लिए बैंकों की आर्थिक प्रभावशाली कार्यों को बताना ताकि ऋण घनुमानों तथा ऋण सीमा निर्धारित करने की वास्तविकता का पता छाल सके।
- (ग) उपरोक्त बातों को व्यान में रखते हुए अगले दो अवधार तीन वर्षों के दौरान शीर्ष समितियों सहित हृषकरण बुनकर सहकारी

समितियों की छट्ठे सम्बन्धी आवश्यकताओं का ग्रन्तीता लगाना और वित्तीय आवश्यकताओं की सीमा को बढ़ाने रूप से बताता और इन सम्बन्ध में प्रायोगिक बुनकर समितियों/शीर्ष समितियों आदि और माथ ही सहकारी वित्तीय बैंकों को मुद्रू करने के लिए उचित सिफारिशें करना।

(घ) सहकारी विभाग, उद्योग विभाग हथकरघा निवेशालय और सहकारी बैंकों के बीच हथकरघा सम्बन्धी वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य स्तर पर और जिला अक्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्ध के लिए व्यवस्था के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और वर्तमान कमियों की, यदि कोई हो, उनका उल्लेख करना और उनमें सुधार लाने के लिए उचित सिफारिशें करना।

(क) उपर्युक्त कार्य विषय से सम्बन्धित अन्य किसी समस्या पर विचार करके सिफारिशें करना।

अध्ययन बल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में हथकरघा वित्त की योजनाओं के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित 53 सिफारिशों की गई थीं। इन सिफारिशों की, शी मणि नारायणस्वामी, हथकरघा विकास प्राप्तक की अध्यभिता में अस्त: मन्त्रालय समिति द्वारा गहराई से जांच की गई। प्रत्येक सिफारिश पर विचार विमर्श करने के परिणामस्वरूप लिये गये निर्णय को परिशिष्ट में दियाया गया है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई अध्ययन दल की सिफारिशों को हथकरघा उद्योग के प्रभारी विभिन्न अभिकरणों और उद्योग के लिये वित्तीय संस्थानक की व्यवस्था करने और विकास के लिये उत्तरदायी अभिकरणों द्वारा कियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

एम० ए० रंगास्वामी, विशेष सचिव

आदेश

प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आवेद दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्र-पति के लिजी और गिलिटी सचिवों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित शेरों के प्रशासनों, योजना आयोग, भारत के भालोक परीक्षक और नियन्त्रक, हथकरघा/उद्योग के राज्य निवेशक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, राज्य शीर्ष सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भी भेज दी जाये।

एम० ए० रंगास्वामी, विशेष सचिव
'परिशिष्ट'

हथकरघा वित्त सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली के पुनर्विस्तोकन के लिये अध्ययन दल की सिफारिशों पर लिये गये निर्णय को दर्शन बाला विवरण।

सिफारिशों का सारांश	दिया गया निर्णय	
1	2	3
1. विभिन्न राज्यों में हथकरघा वित्त योजना का प्रभाव स्पष्ट करने से विभ-कांश राज्यों में योजना की जो काम प्रगति पाई गई है उसका कारण मुख्यतः निम्नलिखित हो कारिता विभाग का सम्बन्ध न होने,	दिनांक 8 जून, 1978 को उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में हुए हथकरघा मंत्री के सम्मेलन में राज्य सरकारों संघ शासित शेरों के प्रशासकों से प्रार्थना की गई है कि बुनकर समितियों के पुनर्विस्तार के लिये तथा छठी योजना की	

1	2	3
		प्रबंधि के द्वारा उनके पुनर्गठन के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये तथा सहकारिता योजना में उनके बारे में 60 प्रतिशत बृद्धि करने को साते का लक्ष्य प्राप्त कर यहां परत्तु जहां तक संभव हो उससे भी अधिक स्तर तक गहराईता योजना में लाने का प्रयत्न करें। बुनकर समितियों को पुनर्जीवित करने तथा नई समितियों गठित करने के लिये राज्य सरकारों के द्वारा योजना के अन्तर्गत भी गई धनराशि का भी उपयोग कर सकती है।

1	2	3	1	2	3	
कार्यक्रम मान्यता में सहकारी भेद के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से बुनकर समितियों को पुनः कार्य-भग बनाने/पुनर्गठित करने के लिए राज्य सरकारे शेयर पूँजीगत सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार की योजना का लाभ उठा सकती हैं (पैराग्राफ 3.7')						
2.	केन्द्रीय धोका की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारे कमजोर हृथकरथा बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों के अधिकार अद्यता में डालने के लिये कमजोर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान की जारी है। कमजोर बुनकर समितियों के लिये भी एक इसी प्रकार की योजना बनायी जाए ताकि वे कनिष्ठ परिस्थितियों के अंतर्गत अपनी अपेक्षा प्रासितियों को बढ़ावा दें जाएं सकें और इस प्रकार बैंकों से वित्त प्राप्त करने के लिये वे पात्र हो जाएं। इन समितियों को सीमान्त सहायता प्रदान करने के लिये भी व्यवस्था की जाए। (वैराग्राफ 3.8')	राज्य सरकारे कमजोर हृथकरथा बुनकर सहकारी समितियों के अधिकार अद्यता में डालने की योजना बनायी ताकि बुनकर बैंक से वित्त प्राप्त करने के पात्र हो सके राज्य सरकारे से प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार इन समितियों को सीमान्त योजना बनाने पर विचार करेगी।		सहकारी भेद के अंतर्गत भाने वाले हृथकरथों के अनुपात को बढ़ाकर कम से कम 60 प्रतिशत कर दिया जाए। इस कार्यक्रम के लिये व्यष्ट सहायता तक तक नहीं मिल सकती जब तक वह कार्यक्रम सक्रिय करने को सहकारी भेद के अंतर्गत लाने से संबंधित नहीं होता। भनः हम यह जोरदार सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारे अधिक सक्रिय करने को सहकारी भेद के भीतर लाने का प्रयास करे (पैराग्राफ 3.10)		
3.	बुनकर समितियों का पर्यवेक्षण करने के लिये उपलब्ध कर्मचारी भी नामांयता: कानूनी प्रयोगित होते हैं। इन समितियों का पर्यवेक्षण करने ले लिये भारत सरकार ने 1958 में नानदंड निर्धारित किये थे। इन नानदंडों में यह प्रावधान था कि हर 10 समितियों के लिये एक पर्यवेक्षक हो और हर 3 पर्यवेक्षकों के कार्य का निरीक्षण करने के लिये एक निरीक्षक हो। हम यह सिफारिश करते हैं कि वे बुनकर समितियों का बारोंको से पर्यवेक्षण करने के निमित्त पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करें। यह कर्मचारी उम विभाग से संबद्ध हों जो हृथकरथा विकास के लिए कार्यक्रम बनाने वाले उसे कार्यान्वयित करने के लिये जिम्मेदार हों। उन्हें चाहिये कि वे बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने वाले बैंकों के पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के साथ भी निकट संपर्क रखकर कार्य करें। (पैराग्राफ 3.9)	स्ट्रीडून। राज्य सरकारों से प्राप्तमात्रा की जा रही है कि इन मापदण्डों के प्राधार पर उचित कार्यवाही करें। कर्मचारियों की नियुक्ति का मानदंड भी रांड़का पर्याप्त राज्य की वास्तविक धाव-रक्षकता पर निर्भर करेगा।	वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय संस्थान, सहकारी प्रबन्ध विषयन और प्रबन्ध के कार्यक्रम आयोजित करें (2) भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण प्रादृश्यक्रम आयोजित करेगा और सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिये व्यष्ट बैंकिंग कालेज पूर्व में हृथकरथा बुनकर सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिये प्रशिक्षण प्रादृश्यक्रम आयोग करेगा। नागरिक पूर्ति व सहकारिता विभाग सहकारी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद की सलाह से सहकारी बैंकों के मध्यस्थर्ता और कनिष्ठ स्तर के प्रशिक्षण के लिये खोलीय सहकारी प्रशिक्षण कालेजों और कनिष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण का आयोजन करेगा।			
		छठी योजना में यह परिस्थिति भी गयी है कि देश में स्थित सिफारिश सं. 1 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय अनुवार।	इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारी बैंकों को एक परिपक्व भेजेगा। आगामी बीमों में हृथकरथा भेद को पर्याप्त मान्यता में धनराशि देने के लिये समूचे देश में सहकारी बैंकों को अधिक से अधिक शामिल करने के लिये हृथकरथा विकास आयुक्त रिजर्व बैंक के समन्वय से उद्यम सहित अभियान प्रायोजित करेगा।			

1	2	3	1	2	3
---	---	---	---	---	---

प्रतः हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्य सहकारी बैंक अपने ही इति में तथा राष्ट्रीय नीति के परिषेक में शिविर बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने में अधिकाधिक योगदान दें। रिजर्व बैंक द्वारा प्रवल्ल अधिग्राहियों को वे केवल अनुपूरक नियियों के रूप में मानें। मध्यवर्ती सहकारी बैंक भी पाव बुनकर समितियों को किये जाने वाले अपने अधिग्राहियों में बड़ोतारी करने क्योंकि उन्हें रिजर्व बैंक से पूरी सीमा तक पुनर्वित प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया है। (पैराग्राफ 3. 13)

7. बैंकों के ब्याज उपवान संबंधी दावों तथा बुनकर समितियों के छूट संबंधी दावों के निपटान में राज्य सरकारें अनुचित विलंब करती रही हैं। प्रतः हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारें वार्षिक नियोजित योजनाओं के लिए इस प्रकार पर्याप्त माला में बजट में व्यवस्था करें कि राज्य सरकारों पर किये जाने वाले ब्याज, उपवान तथा छूट संबंधी दावों की पूर्ति करने के लिए, पर्याप्त राशि हों तथा दावे करने की तारीख से 3 महीनों के भीतर राशि निश्चित रूप से अदा की जा सके। इष्ट की अपेक्षाकृत अधिक माला को देखते हुए आगामी वर्षों में वार्षिक राज्य योजनाओं में भी ब्याज उपवान के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करनी होगी। (पैराग्राफ 3. 14)

8. कुछ एक मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) ग के साथ पहीं जाने वाली धारा 17 (2) (ब्रा०) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए मंजूर भी गयी इष्ट सीमाओं के लिए गारंटी प्रलेख निष्पादित करने में संभ शासित शेखों के संबंध में राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार की ओर से भी विलंब तुम्हा है। प्रतः हम यह सिफारिश करते हैं कि बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए तथा कुटीर भीर लघु उद्योगों के 22 स्पूल समूहों के वित्तपोषण के लिए जिनके संबंध में भी रिजर्व बैंक से पुनर्वित उपलब्ध है, राज्य

स्वीकृत। राज्य सरकारों को तदनुकूल सूचना दे की जायेगी।

स्वीकृत। राज्य सरकारों से यह प्रारंभना की जायेगी कि वे तीन वर्षों की अवधि के लिये एक जारी रहने वाली गारंटी लागू करें।

सहकारी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले अधिग्राहियों के मामले में सरकारें एक ही समय पर लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए बलने वाली एक ही गारंटी निष्पादित करें। (पैराग्राफ 3. 15)

9. मध्यवर्ती सहकारी बैंक के बल उन्हों बुनकर समितियों को अधिकाधिक माला में अधिग्राहित प्रदान कर सकते हैं, जो सक्षम इकाइयां हैं और जिनके पास अपने वैतनिक सचिव नियुक्त नहीं हैं। ऐसी समितियां देश के अधिकांश भागों में धार्म तौर पर पार्या जाती हैं। जब तक समितियों के पास अपने वैतनिक सचिव नहों होते तब तक उनमें अपने कारोबार का विस्तार करने तथा उसे कारोबार ठंग से बलाने की क्षमता नहीं आएगी। हम यह सुझाव देते हैं कि समितियों की कर्मचारियों की नियुक्ति के हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के निमित्त भारत सरकार एक योजना बनाये। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से ऐसी सहायता प्राप्त कर सकती हैं और बाद में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए समितियों की सहायता कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारें अपने वार्षिक योजनागत प्रावधानों से समितियों को प्रबन्धन-तत्त्वगत सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर भी विचार कर सकती हैं। (पैराग्राफ 3. 17)

10. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, उद्योग बुनकरथा निवेशक तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार जोकि उसके बाद इस संबंध में प्राथमिक सहकारी उद्यकरथा बुनकर समितियों को आवश्यक हिवायतें जारी करें।

25 प्रतिशत की सीमा तक पारिश्रमिक की अधिग्राहित आदायगी उन्हें करें। (पैराग्राफ 3. 18)

11. हालांकि बैंकों द्वारा बुनकर समितियों को उत्पादन भीर विपणन संबंधी प्रयोजनों के लिये विद्ये जाने वाले अधिग्राहियों में सम्प्रता की बुनियादी से वृद्धि हुई है, फिर भी, बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले कुल अधिग्राहियों में ऐसे अधिग्राहियों का भूम्भ पिछले

स्वीकृत। उद्येश्य सहित प्रभियान जैसा कि सिफारिश संख्या 6 (पैरा 3. 13) में प्रस्तावित किया गया है और उद्यकरथा विकास आयुक्त के परिवह संख्या, 15015/76

1	2	3
1. तीन वर्षों के दौरान नगरपाल स्थिर रहा है। यह स्थिति बिलकुल ही सतोषज्ञक नहीं है। हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बूमिकर बैंक समितियों का वित्तपोषण करते को प्रत्यधिक प्राप्तिकान्ति दें। वे तथा कृषकों के वित्तपोषण की तरह इन समितियों के वित्तपोषण में भविक मात्रा में अपना योगदान दें (पैराग्राफ 4. 2)	कोष दिनांक 20-11-1976 द्वारा राज्य स्तर समन्वय समितियों जो कि राज्यों में पहले में ही कार्य कर रही हैं, की आमतौर पर नियमित बैठकों द्वारा ये उद्देश्य प्राप्त किये जायेंगे।	14. भागामी पांच वर्षों की प्रबधि में सहकारी बैंक के अंतर्गत आने वाले हृषकरथों के अनुपात को बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर देने के भारत सरकार के कार्यक्रमों के समर्थन में राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अपनी वित्तीय तथा विकासपरक भूमिकाओं को व्यापक बनाना होगा। इस संदर्भ में हम यह सुझाव देते हैं कि ऐसे प्रत्येक मध्यवर्ती सहकारी बैंक को, जिसके परिवालन बैंक के अंतर्गत सक्रिय या नियक्ति 5000 या अधिक करवे भाले हों, बैंक में केवल सहकारी बुनकर समितियों का विकास तथा वित्त पोषण संबंधी कार्य करने के लिए एक प्रलग कक्ष स्थापित किया जाए। इस कक्ष को प्रधिक संसद्या में करघों को सहकारी बैंक के अंतर्गत लाने, छूट प्राप्त करने के संबंध में समितियों को अधिकारिकताओं से अवगत करने तथा समितियों की कठिनाइयों को तत्काल दूर करने में पहल करनी होगी। बुनकर समितियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने तथा उन्हें हृषकरथा/उद्योग निवेशक/पंजीयक और रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी इस कक्ष को निभानी होगी 'पैराग्राफ 4. 5'
2. वर्तमान समितियों का सभम आधार पर पुनर्गठन करते और नयी सभम समितियों का गठन तथा प्रवर्तन करते की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के संबंधित विभागों की है। राज्य सरकारों के इन कार्यक्रमों में राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहा करनी है और सरकारों को भारी मात्रा में उनकी सहायता पर निर्भर रहना होगा। अतः बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी विकासपरक तथा प्रवर्तक भूमिका को व्यापक बनायें तथा विकास कार्यक्रमों में राज्य सरकारों की महिला रूप से सहायता करें (पैराग्राफ 4. 3)	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों द्वारा राज्य सरकारों द्वारा सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिंदायतें भेजेंगी।	भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के नियमित जिला सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिंदायतें भेजेंगी।
3. सहकारी बैंकों के माध्यम से उद्योगों के वित्त पोषण में संबंधित कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की थी '1968' कि प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक द्वारा तथा उन्हें मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा सभम औद्योगिक खंड स्थापित किये जाएं। इस खंड को नीति तथा उससे संबद्ध मामलों पर विशेष रूप से गठित तकनीकी समूहों से मार्गदर्शन देना होगा। परन्तु प्रधिकांश बैंकों में इस कारण हम सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है कि खंड की औद्योगिक संस्थाओं के साथ उनका कारोबार प्रधिक नहीं है, अतः औद्योगिक खंड तथा तकनीकी समूह की स्थापना करना उनके लिए लाभदायक प्रस्ताव नहीं होगा। हम यह सुझाव देते हैं कि बैंकों को इस मामले पर दूरदर्शिता पूर्वक विचार करता चाहिए, ब्योकि वर्तमान समितियों का सभम पुनर्गठन तथा नयी समितियों की स्थापना हो जाने पर वे औद्योगिक समितियों के साथ काफी कारोबार होने की आशा कर सकते हैं (पैराग्राफ 4. 4)	भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के नियमित जिला सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिंदायतें भेजेंगी।	भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के नियमित जिला सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिंदायतें भेजेंगी।
4. उन बुनकर समितियों के मामले में, जिनके समस्त मवस्य गरीब हैं, सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे प्रधिक न सही, परन्तु उच्चतर वित्तपोषण एजेंसियों से जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, कम से कम उसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। प्रधिकांश बैंक इनपने वित्तीय व्योतों से बुनकर समितियों को प्रदान किये गये अर्थों पर प्रधिक दर पर व्याज में है। यह उचित नहीं है। यदि वे रिजर्व बैंक से पुर्ववित सुविधाएं प्राप्त न करें तब भी उन्हें चाहिए कि वे उसी दर पर व्याज से जिस दर पर व्याज लेते हैं तथा इस मामले को टीक करते के लिये उचित कार्यवाही करें।	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों द्वारा सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिंदायतें भेजेंगी। समय-समय पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उन बैंकों के मामलों की जांच करती चाहिए जो हृषकरथा बैंक द्वारा निर्धारित व्याज दर से ज्यादा व्याज दर लेते हैं तथा इस मामले को टीक करते के लिये उचित कार्यवाही करें।	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों द्वारा सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिंदायतें भेजेंगी। समय-समय पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उन बैंकों के मामलों की जांच करती चाहिए जो हृषकरथा बैंक द्वारा निर्धारित व्याज दर से ज्यादा व्याज दर लेते हैं तथा इस मामले को टीक करते के लिये उचित कार्यवाही करें।

1	2	3	1	2	3
पर उन्हें बैंक से पुनर्वित प्राप्त होता भीर यदि वे आहें तो सरकार से उपदान के लिए बाधा करें। हम यह सुझाव देते हैं कि सभी बैंक यह क्रियाविधि अपनाएं भीर यदि कोई बैंक समितियों से अधिक दर पर आज से तो राज्य सरकारों के संबंधित विभाग को इस मामले में उचित कार्यवाही करनी चाहिए (पैराग्राफ 4. 10)	हथकरण विकास कार्यालय को सूचित करें।		रखने के लिए काफी श्रेष्ठता हों तो हम यह सुझाव देते हैं कि राज्य सहकारी बैंक इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतिरिद्वितीय सहायता प्रदान कर उसकी सहायता करें। इससे मध्यवर्ती बैंकों को उन अच्छी कार्यत समितियों को रिजर्व बैंक द्वारा ज्ञान सीमाएं भेजूर किये जाने भी प्रतीक्षा किये बिना ज्ञान सीमाओं का नवीकरण करने में सहायता मिलेगी जो ज्ञान सीमा की अवधि समाप्त होने पर निविष्ट वित्तीय प्रनुशासन का पालन करती है (पैराग्राफ 4. 16)		
17. बुनकर समितियों के विकास में सहायता प्रदूषाचारों के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के उधारों के संबंध में भूतनतम मार्जिन, योरों से झट्टों 1:40 के अनुपात पर संबंध आवधि की जो छूटें दे रखी हैं, उनमें कोई भी सहकारी बैंक समितियों के द्वित पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए कभी न लाये (पैराग्राफ 4. 11)	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक/राज्य सरकारें सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिंदायतें भेजेंगी।		21. प्राथमिक ज्ञान-विद्याका वित्तपोषण स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रनुशासन के अन्तर्गत मध्यवर्ती सहकारी बैंक तब पुनर्वित के लिए पाल नहीं होता जब वर्ष के दौरान उसकी अतिरिक्त राशियां मांग देयताओं के 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएं। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्राथमिक हृषि ज्ञान समितियों तथा बुनकर समितियों को रिजर्व बैंक से पुनर्वित सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। हमारा यह विचार है कि बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए भंजूर की जाने वाली ज्ञान सीमाओं के साथ संबद्ध करने के लिए रिजर्व बैंक के पास कोई संतोषजनक तथा विश्वसनीय कारण नहीं है। अतः हम यह सुझाव देते हैं कि जब तक बुनकर समितियों रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों की दूरी करती है और वे निर्धारित की गयी क्रियाविधि का पालन भी करती हैं, तब तक रिजर्व बैंक इन समितियों का वित्तपोषण करने के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ज्ञान सीमाएं भंजूर करने पर विचार कर सकता है, वाहे भारी मात्रा में विद्यमान अतिरिक्त राशियों के कारण हृषि कार्यों के लिए मध्यवर्ती ज्ञान सीमाएं भंजूर की गयी हों या नहीं परन्तु यह है कि बैंक की वित्तीय स्थिति और कार्य संबंधी स्थिति इतनी विपरीत अवस्था में न हो कि वे उच्चतर वित्तपोषक एजेन्सियों द्वारा प्रदान किये जाने वाले किसी ज्ञान का उपयोग करने में असमर्थ हों। बुनकर समितियों घपने आप में सक्षम हों, कम से कम क्षमता की समावनाओं से युक्त से भीर		
18. प्राथमिक बुनकर समितियों को भंजूर की जाने वाली अतिरिक्त ज्ञान सीमाओं के लिए रिजर्व बैंक ने 25 प्रतिशत का मार्जिन निर्धारित किया है, जब कि नियमित ज्ञान सीमाओं के मामले में उक्त मार्जिन 10 प्रतिशत है। मार्जिनों की यो विभिन्न वर्ते हर्ये अपैचित्यवृक्ष प्रतीत नहीं होती। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि बैंकों द्वारा प्राथमिक बुनकर समितियों को नियमित तथा अतिरिक्त ज्ञान सीमाओं के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अधिकारों पर रिजर्व बैंक 10 प्रतिशत का एक समान मार्जिन निर्धारित करे (पैराग्राफ 4. 12)	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक प्रावश्यक हिंदायतें जारी करेगा।				
19. हम यह सिफारिश करते हैं कि ऐसे मध्यवर्ती बैंकों द्वारा जिनके पास मितियों तथा उनके स्टार्कों का पर्यवेक्षण करने की संतोषजनक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, प्राथमिक बुनकर समितियों को प्रदान की गयी अतिरिक्त सीमाओं की रिजर्व बैंक द्वारा उस हासित में प्रवाप्त प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। जब बैंक अनुपूरक ज्ञान सीमा संबंधी अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करें और बैंकों द्वारा जिन समितियों का वित्तपोषण किया जाता है, वे समितियों सक्षम क्षमता की संभावनावृक्ष हों और उन्होंने पूर्णकालिक वैत्तिक सचिव नियुक्त किये हों (पैराग्राफ 4. 13)	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक प्रावश्यक हिंदायतें जारी करेगा।				
20. यदि मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की स्वाधिकृत निधियां रिजर्व बैंक द्वारा ज्ञान सीमाएं भंजूर किये जाने तक बुनकरों के वित्तपोषण में निवेशों को जारी	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक प्रावश्यक हिंदायतें जारी करेगा।				

1	2	3	1	2	3
27. का निवाह करते के लिए निगम को निरंतर करार दंग गे अनिवार्य निवारित प्रदान नहीं की गयी है, निगम संप्रति अपने निधियों से केवल शिल्प/संग्रहालय बुनकर समितियों द्वारा सहायता प्रदान करता है और प्राथमिक बुनकर समितियों को कोई सहायता नहीं दी जाती। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि भारत सरकार द्वारा निगम को पर्याप्त निधियों प्रदान की जाए, ताकि प्राथमिक बुनकर समितियों द्वारा पूर्जी में अभियान करने के लिए वह वित्तीय सहायता प्रदान कर सके, (पैरा 5.9)।	कि वे पर्यावरण संबंधी व्यवस्थाओं सक्षमता और वित्त की आवश्यकता के संबंध में मजुर हो जाएं रिजर्व बैंक एसे प्रतिमों की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति दे सकता है वर्षों कि समितियों में किये गये नये कारबों के पंजीकरण को हृषकरणा निवेशक/राज्य सरकार का अन्य सक्षम अधिकारी प्रमाणित करे (पैरा 5.15)।				
27. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि इस संबंध में राष्ट्रीय भूकारी विकास निगम द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधाओं का शिल्प बुनकर समितियों प्राथमिक मात्रा में उपयोग करें। यह निगम शिल्प बुनकर समितियों को राज्य सरकारों के जरिए न केवल शो रूमों और गोदामों का निर्माण कार्य करने और उन्हें खोलने के लिए अपितु उनका संवीकरण करने के लिए भी सहायता दे सकता है। (पैरा 5.13)।	यह हो सकता है कि समिति के पाम पंजीकृत कुछ करपों को किसी न किसी कारण से बेकार रखा जाया है। हम यह सुझाव देते हैं कि इन करपों के संबंध में भी पर्याप्त समिति उन करपों को पुनः कार्यरत करना चाहे तो प्रति करणा वित्त की मात्रा के प्राधार पर छूट सीमाएं उन करपों को पुनः कार्यरत करना चाहे तो प्रति करणा वित्त की मात्रा के प्राधार पर छूट सीमाएं बंदूर की जा सकती हैं वर्षों कि करपे कार्य करने की अच्छी स्थिति में हों। हृषकरणा/उद्योग विभाग के क्षेत्र कर्मचारियों की विशेष सिफारिश के प्राधार पर आपितम बंदूर किये जाएं जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि किन कारणों से करपे बेकार पड़े हुए थे और क्या वे प्रति कार्य करने की अच्छी स्थिति में हैं : बैंकों द्वारा प्रदत्त ऐसे अपितम रिजर्व बैंक से प्रतिपूर्ति पाने के लिए पाल हो सकते हैं (पैरा 5.15)।	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की उचित हिदायतें भेजेगा।			
28. हृषकरणा करपे की लागत प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। अतः रिजर्व बैंक द्वारा प्रति करणा निर्धारित वित्त की मात्राओं का आवश्यक निरीक्षण करने के लिए एक तत्त्व बनाया जाना चाहिए। हम यह सुझाव देते हैं कि रिजर्व बैंक स्वयं ही बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए अपेक्षित वित्त की मात्राओं का लागभग तीन बर्षों में एक बार प्रयोग यदि आवश्यक हो तो उसके पहले पुनरीक्षण करे। (पैरा 5.14)।	स्वीकृत / भारतीय रिजर्व बैंक विसम्बर 1978 तक हृषकरणा बुनकर सहकारी समितियों के वित्तपोषण भान्डांड का पुनरीक्षण करेगा तथा इस पुनरीक्षण के आधार पर कोई गई है।	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की उचित हिदायतें भेजेगा।			
29. यह पाया गया था कि कतिपय मध्यवर्ती सहकारी बैंक समितियों का वित्तपोषण वित्त की उन मात्राओं के अनुसार नहीं करते जो रिजर्व बैंक से प्रतिपूर्ति के लिए पाल है। हम यह सिफारिश करते हैं कि मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे प्रति करणा वित्त की मात्रा के अनुसार प्राथमिक बुनकर समितियों को अपने यहाँ पंजीकृत नये करपों के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करें वर्षों	स्वीकृत 1 भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उपयुक्त हिदायतें भेजेगा।	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की उचित हिदायतें भेजेगा।			
30. हम यह सुझाव देते हैं कि जब समितियों को इस संबंध में आवश्यक पर्यावरण व्यवस्थाओं के साथ प्रस्तुत करें तब रिजर्व बैंक उन्हें स्वीकार कर लें और तब उनकी छूट सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाए। परन्तु सामान्यतः रिजर्व बैंक पूर्ण वर्ष के द्वीरान हुए उत्पादन की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रत्यापित उत्पादन के मूल्यांकन सम्बन्धी मानवाङ्क का प्रयोग करें (पैरा 5.17)।	हम यह सिफारिश करते हैं कि नयी बुनकर समितियों और पुनः किशोरील बनायी जाने वाली निविधि समितियों के मामले में बैंकों द्वारा उनकी छूट सम्बन्धी अपेक्षाओं	स्वीकृत। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की उचित हिदायतें भेजेगा।			
31. हम यह सुझाव देते हैं कि जब समितियों को इस संबंध में आवश्यक पर्यावरण व्यवस्थाओं के साथ प्रस्तुत करें तब रिजर्व बैंक उन्हें स्वीकार कर लें और तबुसार उनकी छूट सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाए। परन्तु सामान्यतः रिजर्व बैंक पूर्ण वर्ष के द्वीरान हुए उत्पादन की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रत्यापित उत्पादन के मूल्यांकन सम्बन्धी मानवाङ्क का प्रयोग करें (पैरा 5.17)।	हम यह सुझाव देते हैं कि नयी बुनकर समितियों और पुनः किशोरील बनायी जाने वाली निविधि समितियों के मामले में बैंकों द्वारा उनकी छूट सम्बन्धी अपेक्षाओं	स्वीकृत। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की उचित हिदायतें भेजेगा।			
32. हम यह सिफारिश करते हैं कि नयी बुनकर समितियों और पुनः किशोरील बनायी जाने वाली निविधि समितियों के मामले में बैंकों द्वारा उनकी छूट सम्बन्धी अपेक्षाओं					

1	2	3	1	2	3
			35. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि स्वीकृत । इस सम्बन्ध में मरकारी कर्मचारियों को हृषकरथा भारतीय रिजर्व बैंक महकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उचित विवायतें भेजेगा ।		
	का मूल्यांकन अब तक की तरह एक वर्ष के बजाय उनके कामकाज के पहले दो वर्षों के लिए प्रदत्त प्रति कर्मचार विष की साकार के आधार पर किया जाए और रिजर्व बैंक बैंकों की समितियों को उनके द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति कर दें (पैरा 5.18) ।		35. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि स्वीकृत । इस सम्बन्ध में मरकारी कर्मचारियों को हृषकरथा भारतीय रिजर्व बैंक महकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उचित विवायतें भेजेगा ।		
33.	वर्तमान मानवष्टों के अनुसार शिखर बनकर समितियों की जहां सीमाएं रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित वर्ष के दौरान उनकी प्रत्याशित विकी के 25 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती है । ये सीमाएं इस मनुमान पर आधारित होती हैं कि वर्ष के दौरान कार्यकारी पूंजी की तुलना में आरंगुनी बिक्री होगी । कलिप्य सहकारी समितियों द्वारा यह संकेत किया गया है कि केवल बिक्री की आवश्यक स्थितियों के अन्तर्गत ही यह सम्भव है परन्तु देश में बिक्री की स्थितियों में इतना सुधार नहीं प्राप्त है कि कार्यकारी पूंजी की तुलना में दीन गुनी बिक्री हो सके । अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि रिजर्व बैंक कार्यकारी पूंजी में बिक्री की कुल राशि के अनुपात की आवश्यकता का प्रता लगाने के उद्देश्य से शिखर बुनकर समितियों का विस्तृत अधिकार अध्ययन करे और यदि आवश्यक पापा जाए तो शिखर बुनकर समितियों के लिए जहां सीमाएं संजूर करने से सम्बन्धित मानवष्टों को संशोधित करे (पैरा 5.22) ।	स्वीकृत । यह अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक 30 अक्टूबर, 1978 तक किया जायेगा तथा उसी अध्ययन के आधार पर उचित नियंत्रण किया जायेगा ।	35. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक/राज्य सरकार इस विषय में सहकारी बैंकों को उचित विवायतें भेजेगी ।		
34.	हम यह सिफारिश करते हैं कि रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को हृषकरथा निवेशक या राज्य सरकार के किसी अन्य मध्यम प्राक्षिकारी द्वारा आवायणी के लिए प्रमाणित पिछले तीन महीनों (सम्प्रति यह अवधि दो महीने है) की कुल छूट सम्बन्धी वावों को अधिकार सम्बन्धी समय पर स्वीकार किये गये ऐसे सभी वावों के अन्तर्गत पिछले महीने के अन्त तक की बकाया राशि, इनमें से जो भी कम हो— को राज्य राशि के रूप में स्वीकृत करने की प्रतिपूर्ति कर दें (पैरा 5.24) ।	स्वीकृत । इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों समितियों के विकास के आधार पर उचित विवायतें भेजेगा ।	36. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक/राज्य सरकार इस विषय में सहकारी बैंकों को उचित विवायतें भेजेगी ।		
38.		स्वीकृत । पोलिएस्टर वस्त्रों के उत्पादन के लिये हृषकरथा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा नियत किया गया प्रति करथा का मापदण्ड जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5,000 रुपये प्रति करथा का स्तर नियत किया गया है, में मानव नियम तथा मिश्रित वस्त्र भी शामिल हैं । भारतीय रिजर्व बैंक इन वस्त्रों के उत्पादन के लिये राज्य सरकारों/सहकारी बैंकों को धनराशि का मापदण्ड वर्ताते हुये उपयुक्त परिमाण भेजेगा ।	37. हम यह सुझाव देने हैं कि जो करवे पालिएस्टर धागों को उपयोग में लाते हैं, उनके लिए रिजर्व बैंक विशेष रूप से प्रति करथा 5,000 रुपये के वित की भावा निर्धारित करे । यदि आवश्यक हो तो इस सन्दर्भ में चलाये गये अध्ययन के आधार पर अब वर्ष स्थिति का पुनरीक्षण किया जा सकता है (पैरा 5.27) ।		
39.		स्वीकृत । राज्य सरकारों ने वर्ष 1976-77 से केवल योजना लक्ष्यता से निष्क्रिय सहकारी हृषकरथा बुनकर समितियों के पुनर्गठन/पुनर्स्थापन एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत 60 प्रतिशत सक्रिय बुनकरों को लाया जा सके तथा जहां सम्भव हो इससे अधिक के सक्षय को प्राप्त किया जा सके ।	38. असम, मेघालय, भूबणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा और मणिपुर के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित सहकारी बैंकों ने अब तक बुनकर समितियों के विकास, प्रवर्तन और वित्त-पोषण में दखल नहीं ली है । वस्तुतः इनमें से किसी भी राज्य में अब तक हृषकरथा वित की योजना को कार्यान्वयित ही नहीं किया गया है । हमें यह जानकारी दी गयी है कि इन राज्यों की आविकांश समितियों या तो कमज़ोर हैं या निष्क्रिय । प्रमम में 30 अक्टूबर, 1977 को विद्यमान 1,531 बुनकर समितियों में से लगभग 845 समितियों निष्क्रिय थीं । नागालैण्ड में 15 समितियों में से केवल 3 समितियों		

1	2	3	1	2	3
सक्रिय थी। नियुक्त में स्थित 72 समितियों में से 43 समितियां निष्क्रिय थीं। मणिपुर और मिजोरम में स्थित क्रमशः 382 और 9 समितियों में से क्रमशः 170 और 6 समितियां निष्क्रिय थीं। इन राज्यों में महकारी बोक्र के प्रसरण अनेक बोक्रों का प्रतुपात बहुत कम था और वह नागालैण्ड में स्थित 0.2 प्रतिशत से लेकर मणिपुर में स्थित 6.5 प्रतिशत तक अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न था। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन समितियों का सकाम आधार पर पुनर्गठन/पुनर्निर्माण करने के लिए शीघ्र कदम उठायें। बैकों को अपनी विकासात्मक तथा प्रवर्द्धक की भूमिका को भी व्यापक बनाना चाहिए और अपने बोक्र में दुनकर समितियों के विकास में महायता पहुंचानी चाहिए। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्राप्तिक्रिया के आधार पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से भी अधिलमत कार्रवाई की जानी चाहिए (पैरा 5.28)।	को मंजूर की जाने वाली जहां सीमाओं के उचित उपयोग के रूप में माना जाना चाहिए। जिन प्राप्तिक्रियानकर समितियों ने नियान आईर प्राप्त किये हैं उनकी ओर से नियंत्रण वैक उच्चतर सीमाएँ मंजूर करने पर विचार करें, यदि संबंधित कपड़े की किसी के उत्पादन की प्रथाध्यवस्था का प्रध्ययन करने के बाद समितियों के नियान आईरों को पूरा करने के लिए जहां की प्रधिक मात्रा आवश्यक पायी जाये (पैरा 5.30)।				
39.	समितियों को चाहिए कि वे अपने नियंत्रित जनता किसीको के कपड़े के उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गम्भीर प्रयास करें। बैकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए मंजूर की जाने वाली कार्यकारी पूँजीगत सहायता रिज़र्व बैंक से प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है (पैरा 5.29)।	स्वीकृत। रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक हिसायतें भेज दी जायेंगी।	41.	करणों की खरीद/वारीकरण और आधुनिकीकरण जैसे प्रयोजनों के लिए काफी अधिक उपचान महित मध्यावधि जहां प्रपेक्षित होते हैं। क्षेत्रीक हपकरण बुनकरों की चुनौती की क्षमता काफी सीमित होती है। हमारा यह विचार है कि इन प्रयोजनों के लिए बुनकरों की जिम्मेदारी है। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारें करणों की खरीद, नवीकरण और आधुनिकीकरण में बुनकरों/समितियों की सहायता करने के लिए अपने वार्षिक बजटों में पर्याप्त प्रावधान करें। भारत सरकार को भी इस कार्यक्रम में राज्य सरकारों की महायता करनी चाहिए (पैरा 5.31)।	स्वीकृत। इस सिफारिश को नियान्वित करने के लिये बत्तमान केन्द्र और राज्य योजना के अतिरिक्त नई योजनायें भी बनाई जायेंगी। ऐसे कार्यों के लिये सहकारी बैंकों से मध्यम कानूनिक तथा दीर्घ कानूनिक सहायतार्थ उदार जातों पर ऐसी संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
40.	विचार बुनकर समितियों को जहां सीमाएँ मंजूर करते समय रिज़र्व बैंक नियंत्रित विपणन जहां की आवश्यकताओं को भी हिसाब में लें। जिन वस्तुओं का नियान किया गया है, परन्तु जिनका मूल्य खरीदार द्वारा हीन महीनों तक की अवधि में ध्वन नहीं किया गया है, उसे समितियों द्वारा बैंकों से लिये गये उद्धारों के सम्बन्ध में रक्त राशि के रूप में मानने की प्रनुभति दी जाए। नियान के लिए विशेष किस्म के कपड़े के उत्पादन में अपनी ओर से या समितियों के माध्यम से समितियों द्वारा किए जाने वाले निवेशों को समितियों	स्वीकृत। जहां तक इन शिवार समितियों की नियान जहां प्रावश्यकताओं का भारतीय रिज़र्व बैंक सभी सम्बन्धितों को उचित हिसायते भेजेगा जहां तक प्राप्तिक्रिया दुनकर समितियों का सम्बन्ध है इन समितियों की उपलब्ध सामान्य जहां सीमाओं के साथ-साथ नियान जहां की आवश्यकताओं के लिये नियंत्रित करने शेष 30 नवम्बर, 1978 तक प्रध्ययन कर लिया जायेगा।	42.	कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि अच्छा कार्य करने वाली समितियों के बोक्र में नयी समितियां पंजीकृत की जाएं और ऐसी नयी समितियों का वित्तीयण करने में बैंक उदासीन रहें। यदि नयी समितियों के संगठन में मध्यवर्ती सहकारी बैंक को भी संबद्ध किया जाए तो ऐसी स्थितियों को अवश्य टाला जा सकेगा (पारा 6.2)।	स्वीकृत। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रार्थना की जायेगी कि इस विषय में उचित कार्यवाही करें।
			43.	हमारे विचार में यदि राज्य स्वरीय समितियों में कुछ गैर सरकारी लोगों को भी रख लिया जाये तो समितियों को उनके कार्य संबंधी बहुत से मामलों में सहायता मिल सकती है। हम इस प्रकार के कदम का स्वागत करेंगे। साथ ही राज्य सरकारों पर इस बात	स्वीकृत। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रार्थना की जायेगी कि इस विषय में उचित कार्यवाही करें।

1	2	3	1	2	3
की जिम्मेवारी छोड़ दी जाए कि वैर सरकारी सौभाग्यों को इन समितियों में किस तरह और किस सीमा तक लिया जाए। 'पैरा 6. 3'।			नियों को राज्य सरकारों द्वारा विसीय महायता प्रदान की जाए 'पैरा 6. 9'।		
44. महकारी धोत और अन्य धोतों में विभक्त हृथकरघा धोत पर दृष्टि नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हृथकरघा विकास कार्यक्रमों के नियंत्रण और कार्यालयों के नियंत्रण उनरदायी विभाग अधीनत् हृथकरघा निवेशालय के अधीन हृथकरघा महकारी, संस्थाओं का प्रभाव होना चाहिए। अनकर समितियों के पंजीकरण की जिम्मेवारी भी इसी विभाग पर होनी चाहिए। साथ ही समितियों की अट्ठण संबंधी आवश्यकताओं को नियोजित करने का अधिकार इस विभाग को होना चाहिए जैसे कि तमिलनाडु में विद्यमान है। बैंकों के अट्ठण सीमा मंवंधी प्रावेदनपत्र भी इसी विभाग द्वारा रिजर्व बैंक को प्रेषित किये जाने चाहिए। 'पैरा 6. 6'।	स्वीकृत। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रार्थना की जायेगी कि इस विषय में उचित जार्यवाही करें। भारतीय रिजर्व बैंक उन हृथकरघा/उद्योग निवेशकों को भी स्पष्टीकरण भेजे जिनको उनकी गज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने सहकारी समितियों का पदेन रजिस्ट्रार/अतिरिक्त रजिस्ट्रार घोषित किया है। हृथकरघा उद्योग निवेशक अपने हृथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के अट्ठण सीमा आवेदन पत्र सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रारों को शूष्टि करते हुए सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को भेज सकते हैं।	46. हम यह सुझाव देते हैं कि ऐसे स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रों में, जहां बुनकर समितियों की अधिकता है, संवर्धित मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को चाहिए कि अपने उपनियमों में संशोधन करके भी इन समितियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करें। राज्य महकारी बैंकों के निवेशक मंडलों में शीर्षस्थ/क्षेत्रीय बुनकर समितियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए 'पैरा 6. 10'।			
45. कई बुनकर समितियों के पास स्टाकों का संचयन हो रहा है जिसका कारण बाजार के भागों में गिरावट नहीं, बल्कि समितियों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा ऐसा है जो जल्दी और आसानी से बिक नहीं सकता। इस संदर्भ में समितियों की सहायता के लिए भारत सरकार ने 1956 में प्रत्येक उप पंजीयक के क्षेत्र में डिजाइनरों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया था। हमने देखा है कि नमिलनाडु राज्य हृथकरघा बुनकर समिति ने तकनीकी प्राप्तशण प्राप्त कर्मचारी नियुक्त किये हैं जो प्राथमिक बुनकर समितियों को उन्नादन कार्य में नयी तकनीकों का प्रयोग करने में महायना देते हैं। हमलिए हमारा सुझाव है कि भर्षी शीर्षस्थ बुनकर समितियों प्राथमिक बुनकर समितियों की महायता के लिए नक्काशी की प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी नियुक्त करें। तकनीकी रूप से प्रशिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शीर्षस्थ समिति	स्वीकृत। राज्य स्तर के संगठन को शिखर स्तर पर तकनीकी स्टाफ, की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजना का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए।	47. हम यह सिफारिश करते हैं कि त्रूफि राज्य स्तरीय समितियों अपने राज्यों की परिस्थितियों को अच्छी तरह जानती हैं इसलिए वे एक समिति की कार्यक्रमता के मानदण्ड निर्धारित करें। यदि उक्त कार्य नहीं किया जाता तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा भी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के दुरुप्रयोग की संभावना उत्पन्न हो सकती है। सामान्य मानवण्ड के प्रतुसार एक बुनकर समिति के पास वर्षे भर सक्रिय रूप से कार्य करने वाले 100 करमे होने चाहिए और कम से कम 3. 50 लाख रुपये की कुल वारिष्ठ बिक्री होनी चाहिए। 'पैरा 7. 3'।			
			48. सहकारी हृथकरघा क्षेत्र को जबदंस्त विपणन नीति अपना कर संगठित क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुनकर सहकारी संस्थाओं को उत्पादन की नई विधियों की शपानाना होगा जिससे यह निश्चय हो सके कि उनके द्वारा उत्पादित सामग्री मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की पहुंच के भीतर ही अयोग्य हृथकरघा उन्नादन के प्रयोगकर्ता बड़ी संख्या में ही वर्ग के सोग होते हैं। उक्त दो बातों के संबंध में भारत सरकार का बम्ब उद्योग विभाग हृथकरघा क्षेत्र की सामान्य रूप से और बुनकर सहकारी संस्थाओं को विशेष रूप से महायता दें सकता है। पैरा 7. 4।	स्वीकृत। उत्पाद विकास, विपणन आसूचना और हृथकरघा कपड़े की आंतरिक और बाहरी विक्रय के संवर्धन के अध्ययन को केन्द्रीय योजनाओं में उच्च वरीयता भी जायेगी। इस विषय में राज्य स्तर के संगठनों को आवश्यक वित्तीय सहायता भी दी जायेगी।	

1	2	3	1	2	3
49.	हथकरण और विज्ञी समिति इस मुकाबले पर विचार किया जा रहा है।		बुनकर समितियों को इस उद्देश्य से ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकता है कि हथकरण बुनकर/हथकरण बुनकर समितियों सहकारी कताई मिलों से शेयर प्राप्त कर सके, बशर्ते कि राज्य सरकारें हथकरण बुनकरों के भास्तु में विये ये मुकाबले के अनुसार समितियों को उपदान देने के लिए सहमत हो जायें। पैरा '7.7'		
50.	कताई मिलों के शेयर खरीदने हेतु बुनकरों को ऋण देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक, हथकरण विकास आयुक्त और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के परामर्श से, एक उपयुक्त योजना तैयार करेगा।		हमारी सिफारिश है कि रिजर्व बैंक हथकरण बुनकरों/हथकरण बुनकर समितियों के लिए सहकारी कताई मिलों की ओर से एक ऋण व्यवस्था शुरू करने पर विचार करे जैसा कि सहकारी चौली मिलों के संबंध में किया गया है। यह ऋण उनकी कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 1/4(g), के अन्तर्गत सूत के बंधक/दुष्टबंधक के आधार पर दिया जाए। भारत सरकार भी मिलों को उपदान देने के संबंध में विचार कर सकती है जिससे कि ऋण पर व्याज प्रदा करने का बोझ हल्का हो सके। पैरा '7.10'		सिद्धान्त रूप में स्वीकृत। इस सिफारिश को त्रियांचित करने में आगे वाली विसीय और अन्य काटिनाइयों की भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और जाच की जायेगी। जहां तक सहकारी कताई मिलों को उनकी कार्यशील पंजी पर ऋण इमाद की संजूरी का सम्बन्ध है, भारत सरकार, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से परामर्श लेकर उन योजनाओं की स्पष्टकरता तैयार करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक इस मम्बन्ध में यथा समय उचित कार्यवाही करेगा।
			हम यह सिफारिश करते हैं कि रिजर्व बैंक बुनाई पूर्व और बुनाई के बाद अधिसंस्करण कार्यों के लिए लगाये गये यूटों को चलाने के लिए बुनकर समितियों की ओर से रियायती दरों पर पुनर्वित सहायता प्रदान करे। पर यह सहायता उस स्थिति में दी जाये जब उस यूनिट नष्ट उद्योगों के लिए निश्चित कसोटी पर खरे उतरें। यदि वे लघु उद्योगों की कसोटी पर खरे नहीं उतरते तो उनको रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली पुनर्वित सुविधाओं के लिए उपभोक्ता किसी की महकारी कताई मिलों के समान ही समझा जाए। पैरा '7.12'		स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और सहकारी बैंकों को उपयुक्त हित्रायमें जारी करेगा।

1	2	3
53.	हमारा सुझाव है कि रिजर्व बैंक स्वीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित बूनकार समितियों का वित्तपोषण बैंकों और सहकारी बैंकों को करने की प्रनमति दे सकते हैं। उपर्युक्त हितायते जारी करेगा। ये समितियां अपने सदस्यों को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उचित धनधक्कतम सीमा और मानदण्डों के भीतर उपयोग शृण प्रदान कर सकते। बुनकार समितियों को बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऐसे भविमों को बैंकों की स्वाधिकृत निधियों पर वैध प्रभार के रूप में माना जाए। 'पैरा 7.14'	

एम० ए० रंगास्वामी, विषेष सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th Feb., 1979

Sub:—Study Group to review the working of the Reserve Bank of India Scheme for Handloom Finance.

No. 6(9)/78/Coop.—The Government of India set up on the 28th October, 1977 by their resolution No. 6/7/77-Coop, a Study Group under the Chairmanship of Dr. M. V. Hate, to study in depth the working of Reserve Bank of India Scheme for Handloom Finance and to make suitable recommendations for proper working of the Scheme. The composition of the Study Group was as follows :—

1. Dr. M. V. Hate, Chief Officer, Agricultural Credit Deptt., Reserve Bank of India, Bombay.
2. Shri B. C. Patanik, Dy. Secretary, Banking Wing, Deptt. of Economic Affairs, Govt. of India, Ministry of Finance, New Delhi.
3. Shri M. M. Batra, Director of Textiles, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
4. Shri P. Shankar, Director of Handlooms & Textiles, Government of Tamil Nadu, Madras.
5. Shri S. N. Shukla, Director of Handlooms, Government of Uttar Pradesh, Kanpur.
6. Shri M. P. Pinto, Director of Handlooms & Textiles, Government of Maharashtra, Nagpur.
7. Shri B. B. Mohanty, Director of Handlooms & Textiles, Government of Orissa, Bhubaneswar.
8. Registrar of Cooperative Societies, Government of Bihar Patna.
9. Managing Director of State Cooperative Bank, Karnataka.
10. Managing Director of State Cooperative Bank, Andhra Pradesh.
11. Shri L. V. Sabharishi, Deputy Development Commissioner for Handlooms Member—Secretary

The terms of the reference of the Study Group were as follows :—

- (a) To review generally the working of the scheme for financing of handloom weavers through Co-operative Societies/Banks out of refinance from the Reserve Bank of India and to suggest modifications and improvements in the working of the scheme, if required.
- (b) To study the specific role played by the Central Co-operative Banks and State Co-operative Banks in arriving at the quantum of credit required for financing of handloom weavers and to indicate a more effective role for the banks for the purpose so that the credit estimates and the credit limit applications are realistic.
- (c) In the light of the above, to assess the credit requirements of handloom weavers' co-operative societies including the Apex Societies during the next two or three years and to give a broad indication of the magnitude of financial requirements and in this connection make suitable recommendations in regard to strengthening of the primary weavers societies/Apex Societies etc. and also of the co-operative financing banks.
- (d) To study the present position in regard to arrangements for co-ordination at the State level and district/regional level in regard in handloom financing between the Cooperative Department, Industries Department/ Directorate of Handlooms and Co-operative Banks and to point out the existing inadequacies, if any, and make suitable recommendations for remedying them.
- (e) To consider any other problem which is relevant to the above terms of reference and make recommendations.

The report submitted by the Study Group contained 53 recommendations relating to various aspects of scheme of handloom finance. These recommendations were scrutinized in depth by an Inter-Ministerial Committee headed by Shri Mani Narayanswami, Development Commissioner for Handlooms. The decisions arrived at on each of the recommendations as a result of such consideration are indicated in Annexure.

The recommendations of the Study Group as accepted by Government of India are required to be implemented by various agencies in charge of Handloom Industry and those responsible for development and providing institutional finance for the Industry.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, All Ministries of the Government of India, All State Governments/Union Territories Administrations, The Planning Commission, the Controller and Auditor General of India, State Director of Handlooms/Industries, Registrar of Cooperative Societies, State Apex Cooperative Banks, District Central Cooperative Banks, All Nationalised Banks, National Cooperative Development Corporation.

ANNEXURE

Statement showing the decisions taken on the recommendations of the working of the Reserve Bank of India Scheme for Handloom Finance.

Sl. No.	Recommendation	Decisions
1	2	3
1.	<p>There is conspicuous imbalance in the impact of the Scheme of Handloom Finance in different states. The reasons for the poor progress of the scheme in many states are mainly relatable to the weak structure of the weavers co-operative arising from factors such as lack of co-ordination between Industries Department and the Co-operation Department, the absence of serious efforts to revive the weak or dormant societies and the lack of sufficient promotional interest taken by the financing banks. The structure of the weavers co-operatives at primary and also apex levels in many states is characterised by dormant and weak societies and is not capable of absorbing the refinance facilities provided by the Reserve Bank under the scheme. Many of the societies still do not conform to the pattern of working recognised by the Reserve Bank. They are not organised on production-cum-sale pattern. As on 30 June, 1976 the number of dormant societies in 16 States/Union Territories was more than $\frac{1}{2}$ of the total number of societies and in states like Bihar, Himachal Pradesh, Karnataka, Punjab, Rajasthan, Tripura and Uttar Pradesh the number of dormant societies was between 45 per cent and 94 per cent of the total number of societies. Further, in states like Himachal Pradesh, Rajasthan and Tripura the membership of dormant societies was more than that of active societies and in states like Karnataka, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal the membership of dormant societies was very large. We, therefore, recommend that the Co-operation and Industries/Handlooms</p>	<p>The State Governments/Union Territories Administrations have been requested in the Conference of Handloom Ministers presided over by Union Minister of Industry held on 8th June, 1978 to draw up a time bound programme for rehabilitation of Weavers societies and also their reorganisation during the 6th Plan period and try to achieve not only the target of 6% cooperative coverage but also higher levels of coverage wherever possible. The State Governments may also avail themselves of the provided under the Central Plan Scheme for revitalisation of weavers' societies and for the formation of new societies.</p>

1	2	3
	<p>Department of the State Governments should draw up a time bound programme for the rehabilitation of weavers societies and also their reorganisation where necessary so that at the end of the Sixth Plan period there will be only viable societies which are capable of absorbing the refinance facilities provided by the Reserve Bank under the Scheme for Handloom Finance. The State Governments may avail themselves of the central schemes for share capital assistance for revitalisation/reorganisation of weavers societies with a view to increasing the co-operative coverage of handlooms and handloom weavers. (Para 3.7)</p>	
2.	<p>There is a central sector scheme under which assistance is granted to weak central cooperative banks to write off the bad debts of the members of primary agricultural credit societies. A similar scheme may be formulated for weak weavers societies also to enable them to write off their bad debts under certain circumstances and thus become eligible for finance from the banks. Provision may also be made for managerial assistance to these societies. (Para 3.8).</p>	<p>State Governments may draw up a scheme for writing off the bad debts and losses of the weak handloom weavers' co-operative societies in order to make them eligible for finance from the Banks. The Central Government will consider formulating a scheme of managerial assistance to these societies on receipt of their proposals from the State Governments.</p>
3.	<p>The Staff available for supervision over weavers societies, by and large, is quite inadequate. The norms for supervision over these societies have been laid down by Government of India in 1956. These norms provided that for every 10 societies there should be one supervisor and for every 3 supervisors there should be one inspector to supervise their work. We recommend that the State Governments should appoint adequate staff for close supervision over the weavers societies. The staff must be attached to the Department which is responsible for formulating and implementing the programmes for handloom development. They</p>	<p>Accepted, State Governments are being requested to take appropriate action on these lines. The pattern and scale of staff to be appointed would however depend upon actual needs in each State.</p>

1	2	3
must work in close coordination with the supervisors/inspectors of the banks financing the weavers societies. (Para 3.9).		Registrar of Cooperative Societies in this regard. Motivation campaigns will be organised by the Development Commissioner for Handlooms in coordination with Reserve Bank of India all over the country for the greater involvement of the Cooperative Banks in the financing of the handloom sector to a substantial extent in the coming years.
4. Under the Sixth Plan it is envisaged that the cooperative coverage of handlooms must be raised to 60 per cent of the total number of handlooms in the country. The credit support for this programme cannot be achieved unless the coverage is in respect of active looms. We, therefore, strongly recommend that the state governments should make efforts to bring more number of active looms within the cooperative fold. (Para 3.10).	As at decision on Recommendation No. 1.	
5. Many of the banks in states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Punjab, Haryana and Assam have yet to start getting used to providing finance to weavers societies and handling the scheme for Handloom Finance. We recommend that state cooperative banks and the cooperative department must pay special attention to familiarising the central banks with the Scheme for Handloom Finance. The banks should be in a position to suitably guide, advise and instruct the weavers and the societies about the procedure, disciplines to be observed etc. in the implementation of the scheme. We further suggest that the Reserve Bank/State Governments may organise suitable training courses for the officers of the concerned departments of the State Governments and cooperative banks on the financing of weavers' cooperatives under the scheme. (Para 3.11)	(i) While the Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management will organise programmes for marketing and management. (ii) The Reserve Bank of India will organise Training Courses for higher level officers of the State Governments and the Chief Executives of Cooperative Banks on the Reserve Bank of India Scheme of financing of handloom weavers' cooperative societies in the college of Agricultural Banking at Pune. (iii) The Department of Civil Supplies and Cooperation may also arrange in consultation with the National Council for Cooperative Training, training for intermediate and junior level functionaries of the Cooperative Banks in regional cooperative training colleges and junior training centres.	Accepted. State Government will be informed accordingly.
6. Some of the central banks are not taking due interest in the financing of weavers societies.	Reserve Bank of India will issue a circular to the Co-operative Banks and	Accepted. The State Governments will be requested to execute a single continuing guarantee for a period of three years.

1	2	3
for financing of weavers societies. We, therefore, recommend that the governments should execute a single continuing guarantee for a period of 3 years at a time for the advances proposed to be available of by the state co-operative banks from the Reserve Bank for the financing of weavers societies as well as for financing of the 22 broad groups of cottage and small scale industries for which also refinance is available from the Bank. (Para 3.15).	Accepted. Central Government will formulate a scheme for giving financial assistance to the cooperative societies for appointment of staff. The State Governments will also be requested to consider granting the societies some managerial subsidy for the purpose from their own Annual Plan provisions.	Increased in absolute terms, the proportion of such advances to the total advances made by the banks has been more or less static during the last three years. This is not at all a satisfactory position. We recommend that the state and central cooperative banks should give high priority to the financing of weavers societies. They should involve themselves in an increasing measure in the financing of these societies as in the case of financing of small farmers. (Para 4.2)
9. The control cooperative banks can make advances in an increasing measure only to weavers societies which are viable units and having their own paid staff. Societies not having paid secretaries are common in many parts of the country. Unless the societies have their own paid secretaries, it will not be possible for them to expand and manage their business effectively. We suggest that Government of India may formulate a scheme for giving financial assistance to the societies for appointment of staff. The State Governments may avail themselves of such assistance from Central Government and in turn assist the societies in the appointment of staff. The state governments may also consider granting the societies some managerial subsidies for the purpose from their own annual plan provisions.	(Para 3.17)	12. The reorganisation of existing societies on a viable basis and the organisation and promotion of new viable societies are the responsibility of the concerned departments of the State Governments. In these programmes of the State Governments the state and Central Cooperative Banks have a vital role to play and governments will have to heavily rely on their assistance. It will, therefore, be necessary for the banks to widen their developmental and promotional role and actively assist the State Governments in their developmental Programmes. (Para 4.3)
10. We recommend further that the societies must advance yarn to the weavers to the extent required for the economic working of the warp against one or two sureties only. They should also make advance payment of wages to the weavers at least to the extent of 25 per cent of the value of the total number of knots of yarn issued to them. (Para 3.18)	Reserve Bank of India will write to Director of Industries/Handlooms, Registrar of Cooperative Societies who will in turn issue necessary instructions to the Handloom Weavers' Primary Cooperative Societies in this regard.	13. The working Group on Industrial Financing through Cooperative Banks had recommended (1968) the setting up of a separate industrial section by every state cooperative bank and the bigger among the central cooperative banks. This section is to be guided on policy and allied matters by technical groups set up for the purpose. But many banks have not implemented these recommendation on the group that since their business with the industrial-Cooperative is not much, the setting up of an industrial section and technical group may not be a remunerative proposition. We suggest that the banks must take a long term view of the matter as they can expect adequate business with the industrial societies when once the existing societies are reorganised
11. Though the advances made by the banks to the weavers societies for their production and marketing purposes have	Accepted. Motivation campaigns as proposed at Recommendation No. 6 (Para 3.13) and frequent	Accepted. Suitable instructions will be issued by Reserve Bank of India and State Governments to the Cooperative Banks.

1	2	3	1	2	3
			Even if they do not seek refinancing facilities from the Reserve Bank they should charge only the same rate at which they can get refinance from the Bank if they so desire and claim subsidy from the government. We suggest that all the banks should follow this procedure and if any bank charges a higher rate of interest from the societies, the concerned department of the state governments should take appropriate action in the matter. (para 4.10).		than stipulated by Reserve Bank of India for the handloom sector and take appropriate corrective action in the matter under intimation to Development Commissioner for Handlooms.
14.	The state and central cooperative banks will have to enlarge their financial and developmental roles in support of the Government of India's programmes to raise the Cooperative coverage of handlooms to 60 per cent during the next five years. In this context we suggest that every central cooperative bank in whose area of operations there are 5000 or more looms, active, and dormant, must create a separate cell in the bank exclusively to attend to the work of developing and financing weavers cooperatives. This cell must take the initiative in bringing more number of looms, within the cooperative fold, in explaining to the societies the formalities to be gone through for availing of loans and assist in the financing of the societies in accordance with the prescribed norms and in promptly attending to the grievances of the societies. This cell must also be responsible for collection of data relating to weavers societies and furnishing the same to the Director of Hand looms/Industries/Registrar and the Reserve Bank. (Para 4.5).	Reserve Bank of India and State Governments will send suitable instructions to the District Central Cooperative Banks.	17.	The relaxation granted to the weavers societies by the Reserve Bank with a view to aiding in their growth like lower margin for borrowings, share linking to borrowings at 1 : 40 etc. should not be diluted by the cooperative banks to the detriment of the societies. (Para 4.11)	Accepted. Reserve Bank of India/State Governments will issue suitable instructions to the Cooperative Banks.
15.	We also suggest that in states where there are 30000 looms or more the state cooperative banks should form a separate cell exclusively for attending to the promotions, development and financing of weavers societies and coordinating the activities of central cooperative banks vis-a-vis weavers societies. (Para 4.6).	Reserve Bank of India and State will issue suitable instructions to the State Apex Cooperative Banks.	18.	The Reserve Bank has fixed a margin of 25 per cent for additional limits to be sanctioned to primary weavers societies as against 10 per cent in the case of normal limits. The two different rates of margins appear to us not justified. We, therefore, recommend that the Reserve Bank may prescribe a uniform margin of 10 per cent only for the advances made by the banks to the primary weavers societies both under the normal and additional credit limits. (Para 4.12).	Accepted. Reserve Bank of India will issue necessary instructions.
16.	In the case of weavers societies whose members are all poor, the cooperative banks should provide at least the same facilities which they get from the higher financing agencies if not more. Many banks charge high rate of interest on loans made to weavers societies from their own resources. This is not correct.	Accepted. Reserve Bank of India and State Governments will issue suitable instructions to the State Cooperative Banks. From time to time the Registrar of Cooperative Societies should review the cases of those Banks which charge higher rates of interest	19.	We recommend that the additional limits sanctioned to the primary Weavers societies by the Central banks having satisfactory arrangements for supervision over the societies and their stocks must be reimbursed by the Reserve Bank if the banks submit their supplementary credit limit applications and the societies which are financed by the banks are viable/potentially viable and have appointed full time paid secretaries. (Para 4.13).	Accepted. Reserve Bank of India will issue necessary instructions.

1	2	3	1	2	3
20. If the owned resources of the central cooperative banks are too inadequate to sustain their investments in weavers finance till the sanction of credit limits by the Reserve Bank, we suggest that the state co-operative banks should assist them by providing necessary interim financial accommodation for the purpose. This will also help the central banks in granting renewal of limits to good working societies which observe the prescribed financial discipline on expiry of the period of limit without waiting for sanction of credit limit by the Reserve Bank. (Para 4.16).	Accepted. Reserve Bank of India will issue necessary instructions.		potentially so and have full time paid secretaries to look after their affairs. (Para 4.19).		For weavers covered by PACS/FSS/LAMPS the interest subsidy is to be allowed to these societies do not suffer undue hardship vis-a-vis members of handloom weavers cooperative societies. Provisions for this could be made under the relevant scheme in the annual plan of the State Governments.
21. Under the discipline prescribed by the Reserve Bank for financing the short-term credit structure, the central co-operative bank is not eligible for refinance if its overdues exceed 60 percent of the demand for the year. Hence in such circumstances the primary agricultural credit societies as well as the weavers societies are debarred from refinance facilities from the Reserve Bank. We feel that there are no convincing and cogent reasons for the Reserve Bank to link the sanction of limits for financing weavers societies with the sanction of limits for financing short term agricultural operations. We, therefore, suggest that as long as weavers societies satisfy the norms prescribed by the Reserve Bank and they also follow the prescribed procedure, the Reserve Bank may consider sanctioning credit limits to the central co-operative banks for financing these societies irrespective of whether or not they have been sanctioned short term credit limits for agricultural operations on account of heavy overdues provided however the financial position and working of the banks is not in such a bad condition that they are incapable of absorbing any credit extended to them by the higher financing agencies. The weavers societies themselves should be viable, at least	Accepted. Reserve Bank of India will issue necessary instructions.		We feel that the banks will assume more responsibilities and exercise greater care if the societywise scrutiny of loan applications is vested in them. we, therefore, recommend that the Reserve Bank may consider sanctioning overall credit limits to the central co-operative banks for financing weavers societies on the basis of the lending programmes and past performance of the banks and leaving the responsibility for fixing credit limits to individual weavers societies to the banks themselves on the basis of certain norms laid down by the Reserve Bank. The Bank may lay down the necessary guidelines in this behalf for the guidance of the central cooperative banks and obtain such periodical returns from the banks as may be necessary to monitor the flow of credit. The sanction of overall limits by the Bank may, however, be restricted to only those central banks and weavers societies which have adequate supervising arrangements. (Para 4.23).	Accepted. Reserve Bank of India will issue necessary instructions.	

1	2	3	1	3
24.	We also recommend that the Reserve Bank may consider removing the ceiling fixed for sanction of limit to an apex weavers society at 3 times its owned funds in view of the ceiling that the limit sanctioned to an apex society should not exceed 9 times its disposable owned resources. (Para 4.24).	Necessary action has been taken by the Reserve Bank of India.	27.	National Cooperative Development Corporation has been requested to draw up a detail scheme in this regard.
25.	Of late the state Governments have not been quite earnest in strengthening the share capital of weavers societies. We recommend that the governments give priority consideration to contribution of share capital to weavers societies and revive the scheme in this behalf with appropriate allocation of resources in the Sixth Plan period by taking maximum advantage of scheme under central funds which are available. (Para 5.4).	This is an on-going programme and majority of the States are taking full advantage of this Scheme. All the States are being requested to undertake this programme on top-priority basis.	28.	Accepted. Reserve Bank of India will undertake the first such review of norms of financing handloom weavers cooperative societies by December, 1978 and thereafter reviews will be undertaken as per the recommendations.
26.	Due to various financial constraints the state government may not be able to participate in the share capital of the weavers societies in any big way. The governments must, therefore, be assisted by some financing institutions by giving loans for share capital participation in weavers societies. It appears to us that the National Cooperative Development Corporation is the appropriate agency to assist the state governments for contributing to the Share capital of primary weavers societies. Since the Corporation has not been provided with additional funds on continual and effective basis to take up this responsibility, the Corporation is presently extending assistance to only the apex/regional weavers societies out of its funds and no assistance is being given to the primary weavers societies. We, therefore, recommend that the Corporation may be provided with adequate funds by Government of India to enable it to provide financial assistance for participation in the share capital of primary weavers societies. (Para 5.9).	Accepted in principle. The National Co-operative Development Corporation has been requested to draw up a detailed scheme.	29.	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions to State Governments.
30.			30.	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks.

1	2	3	1	2	3
looms also if the society wishes to activise such looms after some-time, provided the looms are in good working conditions. The sanction of the limit should be on the special recommendation of the field staff of the Department of Handlooms/Industries indicating the reasons why the looms had to remain idle and whether they are now in a good working condition and such advances made by the banks may be eligible for reimbursement by the Reserve Bank. (Para 5.15)			have not developed to such an extent as to make it possible to have more than 3 times the turnover of working capital. We, therefore, recommend that the Reserve Bank may undertake a detailed state-wise study of the apex weavers societies with a view to finding out the practicable ratio of working capital to sales turnover and, if found necessary, revise the norms for sanctioning credit limits for the apex weavers societies. (Para 5.22)		
31. We suggest that when societies submit any concrete and acceptable production programme supported by such supervising arrangements as may be necessary in this behalf, the Reserve Bank may accept the same and their requirements must be assessed accordingly. Normally, however, the Reserve Bank may go by the norm of assessment of anticipatory production at 20 per cent over the production during the previous year. (Para 5.17)	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks.		34. We recommend that the State Cooperative Banks may be permitted by the Reserve Bank to reckon as cover the aggregate rebate claims certified for payment by the Director of Handlooms or the other competent authority of the State Government in the past 3 months instead of 2 months as at present or the actual outstanding under all such claims preferred from time to time as at the end of the preceding month, whichever is less. (Para 5.24)	Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks in this regard.	
32. We recommend that in the case of new weavers societies and dormant societies to be activised, their credit requirements may be assessed by the banks on per loom scale of finance for the first two years of their working instead of one year as at present and the Reserve Bank may fully reimburse the banks of such advances granted by them to the societies (Para 5.18)	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks in this regard.		35. We also recommend that the aggregate of claims presented to the Treasuries/Government Departments in the past 3 months in respect of credit sales of handloom cloth made to Government servants, instead of 2 months as at present may also be reckoned as cover for the borrowings of apex weavers societies. (Para 5.25.)	Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks in this regard.	
33. According to the existing norms, the credit limits of apex weavers societies are fixed by the Reserve Bank at 25 per cent of their anticipatory sales during the year. This is based on the assumption that it is possible to have 4 times the turnover of the working capital during the year. It is pointed out by some apex societies that this is possible only under ideal conditions of marketing but that the marketing conditions in the country	Accepted. This study will be undertaken by the Reserve Bank of India by 30th November, 1978 and appropriate decision taken on the basis of the Study.		36. We recommend that the Registrar as well as the State Cooperative Banks must take early action to ensure that every Central Cooperative Bank complies with the instructions of the Reserve Bank and releases the reserve fund deposits of the weavers societies immediately for their use in the business of the societies. (Para 5.26)	Accepted. Reserve Bank of India/State Governments will issue suitable instructions to the Cooperative Banks over this matter.	
			37. We suggest that the Reserve Bank may as a special case fix the scale of finance at Rs.5000 per loom using polyester fibre so that the banks can start financing the societies	Accepted. The per loom scale of finance fixed for production of Polyester Fabrics by the handloom weavers cooperative societies as fixed at the	

1	2	3	1	2	3	
ties without delay. If need be, the position can be reviewed next year on the basis of studies taken up in this behalf. (Para 5.27)		level of Rs. 5,000 by Reserve Bank of India will cover all man-made and blended fabrics. Reserve Bank of India will issue suitable instruction, circulars to the State Govts./Cooperative Banks indicating the scale of financing for production of these fabrics.		the banks for the purpose are eligible for reimbursement from the Reserve Bank. (Para 5.29)		
38. The Cooperative Banks in the North Eastern States of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura and Manipur have not taken any interest in the development, promotion and financing of the weavers societies. In fact the scheme for handloom finance has not been implemented in any of these States. We are given to understand that the majority of the societies in these States are either weak or dormant. In Assam out of 1531 weavers societies as on 30 November, 1977 as many as to 845 were dormant. In Nagaland out of 15 societies only 3 were active. In Tripura out of 72 societies, 43 were dormant. In Manipur out of 382 societies 170 were dormant and in Mizoram out of 9 societies 6 were dormant. The co-operative coverage of handloom in these States was very low and ranged between 0.2 per cent in Nagaland and 6.5 per cent in Manipur. The State Governments must take early action for the reorganisation/rehabilitation of these societies on a viable basis so that the societies become eligible for finance from the banks. The banks must also widen their developmental and promotional roles and help the growth of weavers societies in their region. The implementation of this programme needs special emphasis on a priority basis and urgent action from the Government of India as well. (Para 5.28)	Accepted. The State Governments have taken up a programme of reorganisation/rehabilitation of dormant handloom weavers cooperative societies since 1976-77 with Central Plan assistance. The programme needs to be stepped up to reach the 60% active coverage and also exceed this level wherever possible.		40. The Reserve Bank may take into account the need for export marketing credit of the apex weavers societies while sanctioning credit limits to them. The value of goods exported but not paid for by the buyers for a period upto 3 months may be allowed to be reckoned as cover for the borrowings of the societies from the banks.	Accepted. As for the expert credit requirements of these Apex societies are concerned, Reserve Bank of India will issue suitable instructions to all concerned.		
39. The societies must make earnest efforts to achieve the targets set for them for the production of Janta varieties of cloth. The working capital requirements granted by	Accepted. Necessary instructions will be issued by the Reserve Bank of India.		41. Purposes like purchase, renovation and modernisation of looms require medium-term loans with high elements of subsidy as the repaying capacity of the handloom weavers is very much limited. We feel that it is the responsibility of the State Governments to assist the weavers and the societies for these purposes. We, therefore, recommend that the State Governments may make adequate budgetary provisions in their annual State plans for assisting the weavers/societies in the purchase, renovation and modernisation of looms. The Government of India should support the State Governments in this programme. (Para 5.31)	Accepted. In addition to the existing Central Plan Scheme and the States schemes, new schemes to give effect to this recommendation would be drawn up. The possibility of securing medium term/long term assistance from Cooperative Banks for such activities on liberal terms should be explored.		
			42. There may arise situations when new societies are registered in the area of good working societies and hence the banks are reluctant to finance	Accepted. The State Government/Union Territories will be requested to associate the Central Cooperative Banks in the		

1	2	3	1	2	3
such new societies. Such situations can very well be avoided if the central cooperative bank is associated in the organisation of new societies. (Para 6.2)		organisation of new societies/revitalisation of dormant ones.		ing the technical staff the apex societies may be granted financial assistance by the State Governments. (Para 6.9)	
43. We feel that the presence of some non-officials on the State level committees may in many cases help the committee in their work. We would welcome such a move leaving it to the State Governments the manner and extent of association of non-officials with such committees. (Para 6.3)		Accepted. The State Government/Union Territories will be requested to take necessary action in this matter.	46. We suggest that in areas where there is concentration of weavers societies, the concerned Central Cooperative Banks should give representation to these societies even by amending their by-laws. Apex/regional weavers societies should be represented on the Board of Directors of the State Cooperative Banks. (Para 6.10)	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions in this regard.	
44. There should not be dual control over the handloom sector segregated into cooperative sector and others. The department, viz., the Directorate of Handlooms which is responsible for the formulation and implementation of handloom development programmes must be in charge of handloom cooperatives. They must be responsible for registration of weavers societies and must have a say in planning their credit requirements as is obtaining in Tamil Nadu. The credit limit applications of the banks may also be forwarded to the Reserve Bank by the same department. (Para 6.6)		Accepted. The State Governments/Union Territories will be requested to take necessary action in this matter. The Reserve Bank of India may also issue clarification to those Directors of Handlooms/Industries who have been declared as the ex-officio Registrar/Additional Registrar of cooperative societies by their respective State Government/Union Territories. Director of Handlooms/Industries can send their credit limit applications of the handloom weavers' cooperative societies direct to the RBI under intimation to the State Registrar of Coop. Societies.	47. We recommend that the State Level Committees who know the conditions in their States better may lay down norms for viability of a society. Unless this is done there may arise chances for misutilization of the various facilities provided by the Central and State Governments. As a general norm we would say that a weavers society should have at least 100 looms working actively throughout the year and have a minimum sales turnover of Rs 3.50 lakhs. (Para 7.3)	Accepted. Suitable guidelines will be issued by Central Government in consultation with the State Government/Union Territories on which constitutes a viable society in a particular State.	
45. Many weavers societies are facing accumulation of stocks not because of any slump in the market but because they are producing cloth which cannot be sold easily or early. It is for helping the societies in this regard that The Govt. of India had suggested in 1956 the appointments of Designors in every Deputy Registrar's Circle. We have noticed that the Tamil Nadu State Handloom Weavers Society has appointed technical staff to assist the primary weavers societies in new production techniques. We suggest that all apex weavers societies may appoint such technical staff in helping the primary weavers societies. For appoint-		Accepted. The State level organisations should take full advantage of the National Cooperative Development Corporation scheme for provision of technical staff at the apex level.	48. The handlooms in the cooperative sector will have to follow an aggressive marketing policy and compete with the organised sector. For this purpose the weavers cooperatives must adopt new techniques of production so as to ensure that what is being produced is acceptable to the consumers. They should also adopt cost reduction programmes so as to ensure that what is being produced is within the reach of middle class and poor class people since they form the bulk of the consumers of handlooms products. In these two matters the Government of India in the Department of Textiles can offer much assistance to the handloom sector in general and to the weavers cooperatives in particular. (Para 7.4)	Accepted. Studies in product development, market intelligence and promotion of internal and external sale of handloom cloth will be given top priority in the Central Plan schemes. In this regard, necessary financial assistance will also be given to the State level organisations.	

1	2	3	1	2	3
49.	In a meeting of the Sub-group on the Main Working Group on Textiles for Handloom and Powerloom Industries held in Bombay, January 1978, a view was expressed that if some preference is shown by Government of India in allotting cotton bales to the cooperative spinning mills, the supply of yarn to weavers cooperatives may improve, since these mills are required to supply yarn to the weavers cooperatives on priority basis. We suggest that Government of India may consider the feasibility of the above suggestion. (Para 7.5)	This suggestion is being examined.	vided the State Governments are agreeable to grant subsidies to the societies as suggested in the case of handloom weavers. (Para 7.7)		
50.	A study in depth undertaken by the Reserve Bank at the instance of the Study Group covering 640 members of 65 weavers societies in 13 districts in the country revealed that the average weaver is not by and large interested in the acquisition of shares of Cooperative Spinning Mills and those who are interested do not have the requisite repaying capacity to enable them to repay the instalments of any medium-term loans that may be granted to them by the Reserve Bank through co-operative channel for acquisition of shares in consumers type of cooperative spinning mill. Such loans can be provided, however, on a selective basis to those weavers who have additional income from sources other than weaving and on the basis of a substantial subsidy from Government, at least to the extent of 33 1/3 per cent to 50 per cent of the value of shares. The loan amount can be suitably deducted by the societies from the wages payable to the weavers. We also recommend that the Reserve Bank may consider the feasibility of extending such facilities to handloom weavers societies for acquiring shares in co-operative spinning mills for handloom weavers/handloom weavers, societies pro-	A suitable scheme for giving loan to the weavers for purchase of shares in spinning mills will be formulated by RBI in consultation with Development Commissioner Handlooms & N.C.D.C	51. We recommend that the Reserve Bank may consider opening a line of credit on behalf of cooperative spinning mills for handloom weavers/handloom weavers societies as in the case of cooperative sugar mills for meeting their working capital requirements against pledge hypothecation of yarn under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act. The Government of India may also consider granting subsidy to the mills so as to bring down their burden of interest on borrowings. (Para 7.10).	Acceptable in principle. The financial and other implications of implementing this recommendation will be further examined by the Government of India and the Reserve Bank of India. As far as granting interest subsidy to Cooperative Spinning Mills in respect of their working capital finance is concerned, the Government of India will work out the modalities of such-schemes in consultation with State Govts./ Union Territories. The Reserve Bank will take appropriate action in due course.	
			52. We recommend that the Reserve Bank may provide refinance facilities at concessional rates on behalf of weavers societies for running their units for pre-weaving and post-weaving processing operations, if such units satisfy the criteria of small scale industries. If they do not satisfy the criteria of small scale industries, they should be treated on par with consumer type of cooperative spinning mills for refinance facilities from the Reserve Bank. (Para 7.12).	Accepted Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the State Governments/Union Territories and Cooperative Banks.	
			53. We suggest that the Reserve Bank may allow the Central Cooperative Banks to finance the weavers societies for granting consumption credit to their members under appropriate ceilings and norms prescribed by the Reserve Bank and such advances granted by the banks to the weavers societies may be reckoned as a legitimate charge on the owned funds of the banks. (Para 7.14).	Accepted. Reserve Bank of India will issue appropriate instructions to State Governments/ Union Territories and Cooperative Banks.	

M. A. RANGASWAMY, Special Secy.

